स्थान पर नमी संरक्षण वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालियों की शुरूआत वर्षा के बहते पानी को रोकने के लिए अवरोध प्रबंध तथा भूमिगत जलभण्डार में वृद्धि करने के साधनों के माध्यम से मनुष्यों तथा पशुधन के लिए पेयजल घरेलू खपत के लिए जल की अधिक उपलब्धता, जीवन रक्षक सिंचाई तथा कृषि मौसमीय क्षमताओं के अनुसार उपयुक्त नकदी फसलों की खेती सुनिश्चित की जाएगी ।

प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परियोजना आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए पनधारा के तीनों स्थान सबद्ध घटकों, नामतः, कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि तथा निकास मार्गों का एक अंगीय भूजल वैज्ञानिक अस्तित्व के रूप में शोधन किया जाएगा ।

वर्षासिंचित क्षेत्र परियोजना 1990–91 से सभी राज्यों तथा दो केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । देश के 30 प्रतिशत से कम कृष्य भूमि तथा सुनिश्चित सिंचाई सुविधा वाले सभी सामुदायिक विकास खंड इस परियोजना में सम्मिलित होने के पात्र होंगे । चुने गए विकासखंडों में से प्रत्येक में 500 से 5000 हैक्टेयर की लघु पनधारा का विकास सतत फार्मिंग प्रणाली के माडल के रूप में किया जाएगा ।

इस नीति के अनुसरण में सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों को 1990–91 से अब तक 317.418 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं ।

Cultivation of Hops in Hilly Areas

548. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Horticulture Board proposed a comprehensive scheme for the cultivation of hops in hilly areas;

(b) if so, the details therof;

(c) whether any hilly areas of Andhra Pradesh are identified for the cultivation of hops by National Horticulture Board; and

(d) whether any proposals for pilot projects are under Government's consideration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b): The National Horticulture Board has no comprehensive scheme for cultivation of hops in hilly areas. However, the Board has approved a proposal recommended by the Government of Himachal Pradesh for development of 50 ha. land under hops and for strengthening hops processing at a total cost of Rs. 51.335 lakh.

(c) and (d): No, Sir.

Formulation of National Seeds Policy

549. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate a National Seeds Policy;

(b) if so, the details therof;

(c) whether it is a fact that some of the multinationals in the seed industry have been exploiting the farmers by charging exhorbitant prices; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b): No, Sir. Question does not arise.

(c) and (d): Seed prices are not being statutorily regulated. Seed producing agencies fix seed prices based on their costs of production and commercial judgement.